सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 2/2022

दिनांक : 18/01/2022

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

प्रिय साथियों ,

विषय : सीजेडआईईए कार्यकारिणी समिति की बैठक का आव्हान

- एलआईसीमें आईपीओ के खिलाफ अभियान को तेज करो
- 19 जनवरी को एलआईसी राष्ट्रीयकरण दिवस पर 'सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करो, एलआईसी को मजबूत बनाओ' संयुक्त कार्यक्रम को सफल बनाओ
- 23- 24 फरवरी 2022 की श्रमिक संगठनों की संयुक्त देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाओ

सीजेडआईईए की कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल बैठक 15 जनवरी 2022 को अध्यक्ष काम एन चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई । इस बैठक में सीजेडआईईए की सितंबर 2021 में हुई पिछली कार्यकारिणी समिति तथा अक्तूबर में हुई सचिव मंडल बैठक के बाद मध्य क्षेत्र में संगठन के अभियानों एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई । बैठक में सर्वप्रथम जबलपुर में 26 वर्ष की युवा अवस्था में लखनादौन शाखा के साथी आदित्य दुबे के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

बैठक में 11 जनवरी को एआईआईईए सचिव मंडल बैठक के निर्णय के अमल पर भी विमर्श किया गया । कार्यकारिणी समिति ने नए साल के मौके पर मध्य क्षेत्र के सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए इस अवधि में किसान विरोधी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के 500 किसान संगठनों के अभूतपूर्व एकता और तमाम आक्रमण तथा 714 से अधिक किसान साथियों की शहादत के बावजूद अटूट प्रतिबद्धता के साथ एक साल 14 दिन तक निरंतर संघर्ष के बाद उन्हें मिली जीत पर किसान आंदोलन का क्रांतिकारी अभिनंदन किया । कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि इस आंदोलन में किसानों की जीत ने देश के समस्त जनवादी आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की है । किसान आंदोलन ने फिर से एक बार यह प्रमाणित किया कि अंतिम शब्द कभी भी मेहनतकश के दुश्मन नही मेहनतकश ही कहेंगे । कार्यकारिणी समिति ने 16 तथा 17 दिसंबर को बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों के भी बैंक निजीकरण के खिलाफ शानदार हड़ताल के लिए बैंक कर्मियों का अभिनंदन किया । कार्यकारिणी समिति ने इस बात पर संतोष जताया कि इस हड़ताल के समर्थन में एआईआईईए के आव्हान पर मध्य क्षेत्र में भी सभी जगह प्रभावी एकजुटता कार्यवाही आयोजित हुई । इस सफल हड़ताल के चलते फौरी तौर पर ही सही सरकार को बैंक कानून में संशोधन का प्रस्ताव संसद के पिछले सत्र में पेश करना संभव नहीं हुआ । कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि करोना की तीसरी लहर से फिर एक बार मध्य क्षेत्र के साथ ही देश भर में स्थितियां असामान्य है । बैठक ने नोट किया कि इसके मुकाबले का एकमात्र उपाय समूची आबादी का वेक्सिनेशन ही है किंतु केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद कि दिसंबर 2021 तक देश की संपूर्ण आबादी का टीकाकरण हो जायेगा, यह लक्ष्य प्राप्त नही हो पाया है, सरकार जिस 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण का दावा कर रही है उन्हे केवल टीके की एक ही डोज मिली है । इसी तरह केंद्र सरकार के आर्थिक बहाली के सभी दावों के विपरीत अर्थव्यवस्था मांग के गहरे संकट का सामना कर रही है और उसका बड़ा कारण लोगों के हाथों में क्रय शक्ति का घटना है ऐसे समय में एकमात्र उपाय सरकार के बड़े निवेश और लोगों के हाथों में क्रय शक्ति बढ़ाने नकद हस्तांतरण की है किंतु सरकार जो राहत पैकेज जारी कर रही है वह केवल उन पूंजीपतियों की ही मदद कर रही है जिनकी इस महामारी के दौरान भी संपत्ति में 250 से 460 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है । सरकार ने इस अवधि में ही एक वित्तीय वर्ष में ही उनके 2.7 लाख करोड़ रुपए के बैंको के कर्ज राइट आफ कर दिए । बैठक ने यह भी नोट किया कि इस आपदा के दौर में भी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों को कौड़ियों के मोल में निजी हाथों में देने का कुचक्र चला रही है । एयर इंडिया की बिक्री में भी यही हुआ, अभी सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की बिक्री में भी यही खेल हो रहा है , जिस कंपनी के पास 1600 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है उसे मात्र 210 करोड़ रुपए में शत प्रतिशत निजी क्षेत्र की कंपनी को बेच दिया जा रहा है । इस संस्थान के श्रमिकों के संघर्ष और यह मामला न्यायालय में जाने के कारण उसे अभी सरकार को रोकना पड़ा है । इसी तरह वोडाफोन के मामले में सरकार उसके द्वारा देय राशि की अदायगी न किए जाने पर उसके 35.8 प्रतिशत शेयर की धारक बनकर उसे घाटे से उबारने को तैयार है । यह दरबारी पूंजीवाद का चरम है , जहां एक ओर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अपना हिस्सा पूंजीपतियों को बेचकर लूट का अवसर उपलब्ध करा रही है और दूसरी ओर वह उन्हें घाटे से उबारने के लिए उनमें जनता का पैसा लगाकर हिस्सा खरीद रही है । कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि एलआईसी के आईपीओ के संबध में

भी सरकार द्वारा दिखाई जा रही तेजी, डी मेट खाते के लिए लगातार हो रही प्रबंधकीय पहल, बीमाधारको के लिए दियें जा रहे विज्ञापन तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों तक भी इसकी पहुंच उपलब्ध कराने किए जा रहे पहल-कदमियों से साफ है कि सरकार इसमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहती। सरकार विनिवेशीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने एन-केन-प्रकारेण यह सुनिश्चित करने में लगी है । कार्यकारिणी समिति ने उपरोक्त सभी विषयों पर व्यापक चर्चा के बाद निम्न निर्णय लिए-

1. एल आई सी के आईपीओ के खिलाफ अभियान को तेज करो

कार्यकारिणी समिति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय इस विषय पर आयोजित कनवेशन में प्रदेश के मुखमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शिरकत कर हमारे आंदोलन का समर्थन किया । कार्यकारिणी समिति ने तय किया कि हमारे इस अभियान को तेज किया जाना चाहिए । अत: जल्द ही मध्य प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का भी प्रयास किया जाए । सभी मंडलों में मुख्य केंद्र के ज़िलों में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएं। एल आई सी के आई पी ओ के खिलाफ विधायकों, पार्षदों, पंचायत आदि सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रबुद्ध जनों से संपर्क कर उन्हे लामबंद किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए, अखबार में लेख, संपादक के नाम पत्र आदि के जरिए सभी माध्यमों का उपयोग कर अभियानों को तेज किया जाए । कार्यकारिणी समिति ने एआईआईईए के निर्णय के अनुरूप सरकार द्वारा आईपीओ जारी करने पर इसके खिलाफ तत्काल एक दिन के देशव्यापी हड़ताल के जरिए सरकार को इसका करारा जवाब देने के लिए साथियों से तैयार रहने का आव्हान किया ।

2. एलआईसी के राष्ट्रीयकरण दिवस पर संयुक्त कार्यक्रम सफल बनाएं

कार्यकारिणी समिति ने संयुक्त मोर्चा के घटक संगठनों से विमर्श कर 19 जनवरी को एलआईसी राष्ट्रीयकरण दिवस पर नुक्कड़ सभा, पर्चा वितरण, मानव श्रृंखला, प्रदर्शनी आदि के जरिए एलआईसी के योगदान का व्यापक प्रचार प्रसार करने और उस दिन को 'सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करो, एलआईसी को मजबूत बनाओ दिवस' के रूप में मध्य क्षेत्र की सभी इकाइयों में मनाने का आव्हान किया । कार्यकारिणी समिति ने 19 जनवरी से लेकर 7 से 10 दिन का एक पखवाड़ा मनाए जाने का आव्हान करते हुए एलआईसी की रक्षा और आईपीओ के खिलाफ एक व्यापक अभियान का आव्हान किया ।

3. 23- 24 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाओ

कार्यकारिणी समिति का स्पस्ट मत था कि चाहे एलआईसी के आईपीओ का मसला हो या आम बीमा क्षेत्र की सार्वजानिक कंपनियों के निजीकरण का , चाहे बैंक के निजीकरण का मसला हो या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की अंधाधुंध बिक्री का, चाहे किसान विरोधी कृषि कानून हो या मजदूर विरोधी श्रम संहिता, यह समग्रता में 'न्यू इंडिया' के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा देश के तमाम सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने के लिए चलाए जा रहे 'सेल इंडिया' परियोजना का ही हिस्सा है और इसका मुकाबला मजदूर वर्ग की व्यापक एकता के साथ ही करना संभव है । कार्यकारिणी समिति ने इसी रोशनी में बीमा कर्मियों से 23-24 फरवरी 2022 को दो दिन की देशव्यापी हड़ताल को अभूतपूर्व ढंग से सफल बनाने जनता के मध्य भी सभी संगठनों के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाने का आव्हान किया । कार्यकारिणी समिति ने यह विश्वास व्यक्त किया कि इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए समाज जारी में हर किस्म की विभाजनकारी कोशिशों को असफल कर हम पूरी एकता के साथ अपने उद्योग और साथ ही अपना और देश का वर्तमान और भविष्य बचाने एकजुटता के साथ हर आंदोलन को कामयाब बनायेंगे ।

कार्यकारिणी समिति ने मध्य क्षेत्र में नए भर्ती के सहायकों के लंबित पैनल के अमल पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए नए साथियों के शत-प्रतिशत संगठन में शामिल होने पर उनका क्रांतिकारी अभिनंदन किया । कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि 2011 में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में स्थायीकरण की प्रक्रिया से वंचित साथियों के संबध में जबलपुर उच्च न्यायालय में संगठन की पहल पर लगाई गई याचिका में निर्णय आने के बाद उसके अमल के लिए संगठन की ओर से क्षेत्रीय प्रबंधन को पत्र लिखे गए तथा प्रबंधन से सतत पहल जारी है । उल्लेखनीय है कि इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्रबंधन ने विस्तृत विवरण जारी किए है ।

बैठक में आंदोलन की खबर, इंश्योरेंस वर्कर की सदस्यता तथ्य वार्षिक विवरण समय पर भेजने सहित अन्य सांगठनिक विषय पर भी चर्चा की गई । कार्यकारिणी समिति ने इन निर्णय के अमल के लिए सभी स्तर पर सभी कमेटियों की बैठक कर जुटने का आव्हान किया । कार्यकारिणी समिति की बैठक को एआईआईईए व सीजेडआईईए के उपाध्यक्ष काम बी. सान्याल ने भी विशेष रूप से संबोधित किया । उन्होंने याद दिलाया कि इस बार का 19 जनवरी एलआईसी के राष्ट्रीयकरण दिवस के साथ ही भारत केमजदूर आंदोलन के द्वारा संयुक्त हड़तालों की प्रारंभ की गई श्रृंखला में 1982 में हुई पहली संयुक्त हड़ताल की 40 वीं वर्षगांठ का दिन है, इसलिए इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है । उन्होंने कहा कि इसलिए 19 जनवरी 2022 को सीटू और किसान संगठन मिलकर मजदूर, किसान एकता दिवस के रूप में भी मना रहे हैं । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी आंदोलन को हमे पूरी ताकत से सफल बनाना होगा और इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि निश्चय ही हम उसमें सफल होंगे क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थाई नहीं है , इसलिए हमारे आंदोलन ही हमारे भविष्य तय करेंगे । कौन जानता था कि किसान जीतेंगे , जो सरकार कहती थी जो निर्णय लेते है पीछे नही हटते लेकिन उसी सरकार को किसानों ने पीछे हटने मजबूर किया । उन्होंने पूरी एकता के साथ आगे बढ़ने का आव्हान किया ।

हमें विश्वास है कि मध्य क्षेत्र के हमारे साथी इन निर्णयों को लागू करते हुए आगामी आंदोलनों को शानदार रूप से सफल बनायेंगे ।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव